नं. जेड-14014/1/2021-जीसी (ई-3010921)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 20. 07.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जून, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को जून, 2021 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा
(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

माह जून, 2021 के दौरान भूमि संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों का मासिक सार

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 28.06.2021 को विभाग के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की समीक्षा की।

व्यापार करने में आसानी के संपत्ति संकेतक के पंजीकरण के हितधारकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रमश: दिनांक 19 जून, 2021 और 24 जून, 2021 को ऑनलाइन सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित की गई।

सचिव (एलआर) की उपस्थिति में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्चुल मोड के माध्यम से दिनांक 23.06.2021 को छत्तीसगढ़ में विशिष्ठ भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को प्रारंभ किया गया।

ई-न्यायालय के साथ भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डाटाबेस का संयोजन संबंधी समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में दिनांक 09 जून, 2021 को ई-न्यायालय के साथ भूमि अभिलेख तथा पंजीकरण डाटाबेस का संयोजन संबंधी समिति की बैठक आयोजित की गई।

अपर सचिव (एलआर) ने राजस्थान राज्य में डीआईएलआरएमपी, यूएलपीआईएन, एनजीडीआरएस के संदर्भ में पंजीकरण प्रक्रिया, स्वामित्व की स्थिति, सिविल न्यायालय (ई-न्यायालय) के साथ भूमि अभिलेख और पंजीकरण के संयोजन के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जयपुर में दिनांक 21 जून, 2021 को राजस्थान सरकार के i) बंदोबस्त आयुक्त, ii) मुख्य सचिव (राजस्व) और iii) सचिव (पंचायती राज), साथ बैठकें की।

सचिव (एलआर) ने विभाग की रिवार्ड (आरईडब्ल्यूएआरडी) मूल्यांकन क्षेत्र में हुई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 10.06.2021 को एक बैठक की। इसके अलावा, विश्व बैंक एवं सहभागी राज्यों के साथ सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2021 को एक अन्य बैठक आयोजित हुई जिसमें रिवार्ड परियोजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, आज की तारीख तक कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत)-1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} में से 4843 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। अब तक 2940 परियोजनाओं के एंड लाईन मूल्यांकन का कार्य पूरा किया गया है।